प्रेषक.

ओम प्रकाश, सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां,

उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः—1 देहरादून दिनॉक 14 जनवरी, 2009 विषयः— चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के लिये सहकारी सहभागिता योजना (एस०सी० एस०पी०) के अर्न्तगत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 5320 / नियो० / सहभागिता योजना / 2008—09 दिनांक 16.10.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 में सहकारी सहभागिता योजना (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों, आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष भारत सरकार / नाबार्ड से 2 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये जाने वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु रू० 37.00 लाख (सैत्तीस लाख रूपये मात्र) की धनराशि निम्नाकिंत शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

(1) उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 519/XIV-1/2008 दिनांक 22.07.2008 में उल्लिखित शर्तों/विवरण के अनुसार ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त क्लेम के सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त निबन्धक स्तर से सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा एवं अग्रिम

भुगतान अनुमन्य नही होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक,

सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों / उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केंवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के उपादान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि ब्यय न की जाय,

जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग / शासन

तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों / निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य / मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन / समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(8) उक्त योजना का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार दिनांक 31.03.2009 तक व्यय सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा

अवशेष धनराशि 31.03.2009 को शासन को समर्पित की जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय 03- सहकारी सहभागिता योजना-00-50-उपादान के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०संख्या- 215(P)/XXVII-4/2008 दिनांक

05.01.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(ओम प्रकाश) सचिव।

संख्या:-885 (1)/XIV-1/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन।

3-वित्त अनुभाग-4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, विभाग उत्तराखण्ड शासन।

4- अपुर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

'६ निदेशक, एन0आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराचंल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी ।

8- समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

9-समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लिं0, उत्तराखण्ड।

10- गार्ड फाईल ।

A STATE

अनुसचिव।